

फल अहकाम  
 धौ ल वोर ड / बनीम / शाली व रुम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अम्भेर  
 मुख्यालय-जयपुर

08/2024

(ली. शा. व. रू.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24/6/24	<p>पत्रावली पेशा डक   उम्पपुत्र 540                      पत्रावली वास्ते बहल जा. पा. ली.                      आ. व. पूरानुका (दिनांक 03/7/24)                      को पेशा है।</p>	
03/7/24	<p>आज दिनांक 03/07/24 को पत्रावली पेश हुई। अधिकाधिक संघ द्वारा आज्ञा कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। अन्य कार्य में वास्ते/अवकाश/पु. व. उक्त पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/7/24 को पेश हों।</p>	
16/7/24	<p>पत्रावली पेशा डक। अधिवक्तागण उम्पपुत्र उपस्थित। बहल जा. पा. ली. आ. व. पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश। निर्णय दिनांक 25/7/24 को पेशा है।</p>	
25/7/24	<p>पत्रावली पेशा डक। अधिवक्तागण उम्पपुत्र उपस्थित। बहल जा. पा. ली. आ. व. के तथ्यों पर नतीजा दिया व पत्रावली को अवलोकन किया। उम्पपुत्र कारण के प्रस्तुत तथ्यों के पत्रावली के समाप्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आलेखित शक्ति वादगुप्त आ. व. नं. 357, 358, 359 (हाल ख. नं.) कल (वकालत) वि. उ. कल (वकालत) 1.34 है। अज्ञातगण के प्रवेज यांचे पु. व. रा. व. के विवेचन</p>	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अम्भेर  
 मुख्यालय-जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अम्भेर  
 मुख्यालय-जयपुर

**फर्द अहकाम**  
 घोषण भवन नाम शाली व भवन

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

केस संख्या 08/2024

(टी. 378)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/11/24	<p>प्रक्रिया के अन्तर्गत आवंटन / निपकन शुल्क भूमि है। जिससे प्रस्तुत इस्तीफेजान अनुसार प्राथमिकता का प्रथम दृष्टया कोई सम्बन्ध सरोकार प्रदर्शित नहीं होता है। ना ही प्राथमिकता द्वारा अनधिकृत भूमि वादाग्रत के संदर्भ में अपनी हानि/अधिकारिता अथवा हितकारीता से हानि में कोई मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही प्राथमिकता अथवा प्राथमिकता के पूर्वजों के नाम का पूर्व में राजस्व रिकार्ड में इन्ड्रान का कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया प्राथमिकता का पुस व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तताप शक्ति प्राथमिकता के पुस में प्रमाणित नहीं होती है। प्रस्तुत इस्तीफेजान अनुसार भूमि प्राथमिकता अथवा प्राथमिकता के पूर्वजों के नाम के राजस्व रिकार्ड में इन्ड्रान नहीं रही है। अतः प्राथमिकता का प्राधान्य प्रमाणित किम्वद्वारा पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p>(वित्त निर्णय पृथक से तैयार कर रखा है) परवली फिलहाल शमाट प्रेषण 25 नवंबर से कम हो। काद तदनुसार शीघ्र दफतर हो।</p>

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
 न्यायालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्रीमती श्यामा राठौड  
प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या : 08/2024  
निर्णय दिनांक : 25.07.2024

1. धोलु पुत्र स्व. महादेव
  2. गोपाल पुत्र स्व. महादेव
  3. भगवान पुत्र स्व. महादेव
  4. सुवा पुत्र स्व० भूरा
  5. सुल्तान पुत्र जगन्नाथ
  6. हनुमान पुत्र जगन्नाथ
  7. लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ
  8. शिवदान पुत्र जगन्नाथ
- समस्त जातियान गुर्जर समस्त निवासियान ग्राम स्यारी तहसील आमेर जयपुर।

बनाम

1. घासी पुत्र चौथू
2. कालू पुत्र चौथू
3. श्योदान पुत्र चौथू

-मुख्य अप्रार्थीगण

4. रामचन्द्र पुत्र बट्टी
5. भेरु पुत्र चौखला
6. कालू पुत्र भगवान
7. रामेश्वर पुत्र भगवान
8. ग्यारसी पुत्र सुणाराम
9. रामकरण पुत्र सुणाराम

- समस्त जातियान गुर्जर निवासी ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर।  
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जयपुर।  
11. उप पंजीयक कार्यालय, आमेर तहसील, आमेर जिला जयपुर।

-अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा  
निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से वाके ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 357, 358, 359 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.34 है. के सन्दर्भ में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि (विवादित भूमि) का मूल साबिक खसरा न. 77 रकबा 171 बीघा था। जिसकी 6 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। जिसके आधार पर उक्त 6 बीघा भूमि का पक्षकारान के पूर्वजो के कब्जाकाश्त के रूप में नवीन खसरा न 77/5 के रूप में पृथक पर्चा/खाता कायम किया गया। जिसका अंकन खसरा गिरदावरी संवत 2024-2034 में किया गया। जिसके पश्चात उक्त भूमि के नवीन/हाल खसरा न. 357, 358, 359 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.34 है. कायम किए गए है। जिस पर अपने पूर्वजो के निधन पश्चात पक्षकारान विरासत के आधार पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। पक्षकारान के पूर्वजो में अप्रार्थीगण का पितामह चौथू पुत्र रामदेव राजस्व विभाग में कर्मचारी था। जिसके द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत कर उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि ख.न. 77/5 रकबा 6 बीघा सम्पूर्ण को स्वयं के अकेले के नाम नियमन करवा कर स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज करवा ली गई। जिसकी जानकारी मिन प्रार्थीगण के पूर्वजो को नहीं हुई। उक्त भूमि ख.न. 77/5 के हाल ख.न. 357, 358, 359 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.34 है. की खातेदारिता चौथू पुत्र रामदेव के वारिसान कालू, घासी, श्योदान 1/3-1/3-1/3 हिस्सा के रूप में दर्ज अंकित है जबकि भूमि में प्रार्थीगण 01 ता 8 व अप्रार्थी 4 ता 10 का भी हिस्सा अपने पूर्वजो के अंकित हिस्सानुसार निहित है। जिसके बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अप्रार्थीगण 1 ता 3 के गलत इन्द्राज को प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण 4 ता 10 के निहित हिस्सानुसार दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में निरन्तर गलत अंकन एवं इन्द्राज के आधार पर भूमि गलत रूप से मात्र अप्रार्थीगण 1 ता 3 के नाम दर्ज अंकित है जबकि

वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकार अपने पूर्वज/पितामह के हिस्सानुसार काबिज होकर वर्तमान में भी काशत करते आ रहे हैं तथा पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में सभी पक्षकारान के पूर्वजो के नाम हिस्सेनुसार दर्ज अंकित है व इसी अनुरूप सभी पक्षकारान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। जिससे प्रार्थीगण स्वयं के निहित हिस्सानुसार घोषणा/दुरुस्ती कराने के अधिकारी है। उल्लेखित वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में हुए गलत इन्द्राज एवं अंकन के उक्त तथ्यो की प्रार्थीगण को पूर्व में जानकारी नहीं थी, परन्तु वर्तमान में गाँव में रिंग रोड हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही के संदर्भ में तथा राजस्व रिकॉर्ड में विरासत के नामांतरण की कार्यवाही हेतु जमाबंदी की प्रति प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के पिता का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई। जिसके बाबत अप्रार्थीगण 1 ता 3 से बात करने पर अप्रार्थीगण द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्ती का आश्वासन दिया गया परन्तु प्रार्थीगण के निरन्तर निवेदनो के उपरान्त भी रिकॉर्ड में अंकित गलत इन्द्राज को दुरुस्त नहीं कराते हुए दिनांक 04.02.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट इंकार कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण मय प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज निर्बाध रूप से निरन्तर भूमि पर काबिज रहे हैं जिनके उपरान्त पक्षकारान निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। जिससे यदि अप्रार्थीगण को ता फ़ैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कृषि भूमि के हिस्से की कब्जेशुदा आराजी पर अविधिक प्रक्रिया अपनाकर नाजायज रूप से कब्जा कर उन्हें (प्रार्थीगण) बेदखल कर देंगे तथा भूमि को हस्तांतरित कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण अपने पूर्वजो से प्राप्त हक हिस्से की कब्जेकाशत की भूमि एवं मकानात के शांतिपूर्ण उपयोग-उपभोग व अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो जावेगें तथा प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद/प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीन भूमि हाल आ.ख. नं. 357, 358, 359 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 1.34 है. वाके ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर का विक्रय, हस्तांतरण आदि ना करे तथा प्रार्थीगण को अपने हिस्सानुसार प्रचलित कब्जाकाशत व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा/अवरोध कारित ना करें।



अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण ने मिथ्या व आधारहीन अंकित किये हैं। प्रार्थीगण के किसी भी पूर्वज का खसरा नं. 77/5 पर कभी कोई कब्जा काशत अथवा हक अधिकार नहीं रहा है न ही कभी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग ही किया गया है अपितु भूमि खसरा नं. 77 रकबा 171 हैक्टर सिवाय चक भूमि थी जिसकी 6 बीघा भूमि के हिस्से पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता चौथू पुत्र रामदेव का निरंतर कब्जा काशत रहा तथा उनका उक्त भूमि पर निरंतर काबिज होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण मानते हुये उन पर पेनल्टी लगायी गयी तथा उनके द्वारा समय समय पर उस पेनल्टी का भुगतान किया गया था। अप्रार्थीगण के पिता स्व. चौथू का भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि पर लगातार कब्जा काशत अतिक्रमण मानते हुये राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अलॉटमेंट कमेटी के एडवाईजरी कमेटी के द्वारा प्रार्थी के पिता स्व. चौथू का भूमि खसरा न. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि को एडवाईजरी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1972 को आवंटन कर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता के पक्ष में आवंटन कर नियमन कर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काशतकार के रूप में दर्ज अंकित कर दिया तथा उनके नाम से पर्चा लगान जारी कर दिया गया। तब से ही अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन चला आ रहा था तथा दौराने अवधि बंदोबस्त खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा के नये खसरा नं. 357 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नं. 358 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नं. 359 रकबा 0.60 हैक्टर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित चली आ रही है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव द्वारा अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर काबिज काशत होकर भूमि का बिना किसी बाधा व रुकावट के उपयोग, उपभोग व कब्जे काशत करता चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक वारीसान में उनके पुत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम विरासत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित चला आ रहा है तथा वे ही उक्त भूमि पर काबिज होकर कब्जा काशत करते चले आ रहे हैं। जिससे प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कभी भी वादग्रस्त भूमि से संबंध व सरोकार नहीं रहा है। न ही उनका कभी भी कब्जा काशत ही रहा है। न ही उनके द्वारा कभी कोई लगान ही अदा किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता तथा चौथू पुत्र रामदेव का भूमि खसरा न. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि पर लंबे अरसे से सिवाय चक भूमि पर कब्जा काशत होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर उन पर अतिक्रमण के आधार शास्ति अधिरोपित की गयी थी तथा उनके द्वारा उक्त शास्तियों को समय-समय पर जमा करवाया गया था तथा स्व. चौथूराम का उक्त भूमि पर लंबे अरसे से कब्जा काशत मानते हुये राजस्व विभाग द्वारा अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा उनके पक्ष में विधिवत रूप से उक्त

सहायक कलेक्टर (प्रा.पत्र ट्रेक) आमेर  
न्यायालय-जयपुर

भूमि का आवंटन नियमन करने की सिफारिश की गयी थी तथा उस सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थी के पिता स्व चौथूराम पुत्र रामदेव के नाम से भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि 1972 में आवंटन नियमन की गयी थी। जिससे उक्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम नहीं रही है न ही कभी भी उनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काशत ही रहा है। विवादग्रस्त भूमि के खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 पर कभी भी प्रार्थीगणों के पूर्वजों का कब्जा काशत नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता चौथू पुत्र रामदेव काबिज होकर निरंतर काशत करता चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 ता 3 निर्बाध रूप से बिना किसी व्यक्ति के हक हिस्से के उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम नहीं रही है न ही कभी भी उनका कब्जा काशत ही रहा है। जब प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काशत ही नहीं रहा, न ही राजस्व रिकॉर्ड में कभी कोई अंकन ही नहीं रहा तो प्रार्थीगण का विरासत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने का कोई आधार ही उत्पन्न नहीं होता है। भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा की भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वजों पितामह, पिताजी का कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। न ही कभी उनके नाम कोई खतौनी ही रही है। जब प्रार्थीगण के पितामह, पिता आदि का कभी कब्जा काशत नहीं रहा है, न ही कभी राजस्व रिकॉर्ड में कभी अंकन रहा है, न ही उनके नाम से खतौनी रही है तो उक्त भूमि भूरा, महादेव, बट्टी का हिस्सा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, न ही भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा पर अप्रार्थीगण के पिता के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध, सरोकार, हित व अधिकार निहित रहा है। भूमि खसरा नं. 77 रकबा 171 हैक्टर सिवाय चक भूमि थी जिसकी 6 बीघा भूमि के हिस्से पर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता चौथू पुत्र रामदेव का निरंतर कब्जा काशत रहा तथा उनका उक्त भूमि पर निरंतर काबिज होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण मानते हुये उन पर पेनल्टी लगायी गयी तथा उनके द्वारा समय समय पर उस पेनल्टी का भुगतान किया गया था अप्रार्थीगण के पिता स्व. चौथू का भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि पर लगातार कब्जा काशत अतिक्रमण मानते हुये राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अलॉटमेंट कमेटी के एडवाइजरी कमेटी के द्वारा प्रार्थी के पिता स्व. चौथू का भूमि खसरा न. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि को एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1972 को आवंटन कर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता के पक्ष में आवंटन कर नियमन कर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काशतकार के रूप में दर्ज अंकित कर दिया तथा उनके नाम से पर्चा लगान जारी कर दिया तब से ही अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन चला आ रहा था तथा दोराने अवधि बंदोबस्त खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा के नये खसरा नं. 357 रकबा 0.69 हेक्टर, खसरा नं.358 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नं. 359 रकबा 0.60 हेक्टर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित चली आ रही है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू पुत्र रामदेव द्वारा अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर काबिज काशत होकर भूमि का बिना किसी बाधा व रुकावट के उपयोग, उपभोग व कब्जे काशत करता चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक वारीसान में उनके पुत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम विरासत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित चला आ रहा है तथा वे ही उक्त भूमि पर काबिज होकर कब्जा काशत करते चले आ रहे हैं। जिससे प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कभी भी वादग्रस्त भूमि से संबंध व सरोकार नहीं रहा है। न ही उनका कभी भी कब्जा काशत ही रहा है। न ही उनके द्वारा कभी कोई लगान ही अदा किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता तथा चौथू पुत्र रामदेव का भूमि खसरा न. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि पर लंबे अरसे से सिवाय चक भूमि पर कब्जा काशत होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर उन पर अतिक्रमण के आधार शास्त्रि अधिरोपित की गयी थी तथा उनके द्वारा उक्त शास्त्रियों को समय-समय पर जमा करवाया गया था तथा स्व. चौथूराम का उक्त भूमि पर लंबे अरसे से कब्जा काशत मानते हुये राजस्व विभाग द्वारा अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा उनके पक्ष में विधिवत रूप से उक्त भूमि का आवंटन नियमन करने की सिफारिश की गयी थी तथा उस सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थी के पिता स्व चौथूराम पुत्र रामदेव के नाम से भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि 1972 में आवंटन नियमन की गयी थी जिससे उक्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम नहीं रही है न ही कभी भी उनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काशत ही रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वजों पितामह एवं अन्य किसी का भी भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा अथवा हाल खसरा नं. 357,358,359 पर कभी काबिज काशत रहे हैं, न ही वर्तमान में प्रार्थीगण का कोई कब्जा काशत ही है। जब प्रार्थीगण के पूर्वजों का ही कभी वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा, काशत व राजस्व रिकॉर्ड में कभी कोई अंकन ही नहीं रहा है तो प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा अप्रार्थीगण के पिता को जरिये आवंटन पत्र आवंटित हुयी थी तथा आवंटन होने के पश्चात अप्रार्थीगण के पिता का नाम वतौर खातेदार काशतकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन रहा है तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर



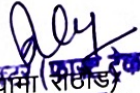
निरंतर, लगातार काश्त करते चले आ रहे थे। दौराने अवधि बंदोबस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा के हाल खसरा नं. 357,358,359 बने। इस प्रकार अप्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता निरंतर, लगातार उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार रहे है तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी बाधा व रुकावट के कब्जे काश्त करते रहे है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 ता 3 उक्त भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा व रुकावट के कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण तथा उनके पूर्वजों का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा, काश्त, हक व अधिकार निहित नहीं रहा है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि चौथू पिसरान रामदेव राजस्व विभाग में नहीं थे बल्कि कृषि विभाग में कर्मचारी थे उनको राजस्व विभाग की जानकारी नहीं है, वह मात्र कृषि विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत था। चौथू पिसरान रामदेव ने किसी से कोई मिलीभगत व सांठगांठ नहीं की बल्कि भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा पर काफी वर्षों से काबिज होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि अतिक्रमण मानते हुए उन पर पेनल्टी अधिरोपित की गयी तथा आवंटन कमेटी की सिफारिश के आधार पर उक्त भूमि पर निरंतर काबिज मानते हुये उसके पक्ष में विधिवत रूप से भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा दिनांक 31.02.1972 को आवंटित कर नियमन कर दिया तथा उसके नाम पर्चा लगान जारी कर दिया तथा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार के रूप में नाम दर्ज अंकित कर दिया तब से ही रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार के रूप में बिना किसी बाधा व रुकावट के अप्रार्थीगण की जानकारी में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था तथा स्व. चौथू के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज अंकित चला आ रहा है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों को भली भाँति रही है। प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 से कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है न ही प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों ने कभी कब्जा काश्त ही किया है। जब वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा काश्त ही नहीं रहा तो उनका उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने का आधार ही नहीं है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजों को पूर्ण रूप से जानकारी रही है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि चौथू राम के नाम राजस्व विभाग द्वारा सन 1972 में आवंटित कर नियमन किया गया था तब से स्व. चौथू उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में रहा है तथा वही काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण द्वारा वर्णित तथ्य मिथ्या आधारों पर आधारित होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 कभी भी प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रही है न ही प्रार्थीगण के पूर्वजों व प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा ही रहा है बल्कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू के नाम आवंटन शुदा भूमि है जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार स्व. चौथू पुत्र रामदेव अपने जीवनकाल तक रहा है तथा उसके द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता रहा है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होकर चला आ रहा है। जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को किसी भी अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबंद करवाने के कोई कानूनन अधिकारी नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का कभी भी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। न ही वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त ही रहा है जब प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कभी कोई संबंध सरोकार ही नहीं रहा है तो उनके द्वारा उक्त भूमि पर रिकॉर्ड खातेदार को कानूनन पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। न ही प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार की अपूर्ण्य क्षति कारित हो रही है बल्कि प्रार्थीगण को पाबंद किये जाने से उनको अप्रार्थीगण 1 ता 3 को ऐसी अपूर्ण्य क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी प्रकार संभव नहीं होगा क्योंकि अपूर्ण्य क्षति का विदू प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में पूर्णतः साबित है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नं. 357,358,359 कभी भी प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं रही है न ही प्रार्थीगण के पूर्वजों व प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा ही रहा है बल्कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 77/5 रकबा 6 बीघा भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 3 के पिता स्व. चौथू के नाम आवंटन शुदा भूमि है जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार स्व. चौथू पुत्र रामदेव अपने जीवनकाल तक रहा है तथा उसके द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता रहा है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज होकर चला आ रहा है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।





हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत तथ्यों व पत्रावली के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त अप्रार्थीगण सं 1 ता 3 के पूर्वज चौथू पत्र रामदेव की विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत आवंटन/नियमनशुदा भूमि है जिससे प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार प्रदर्शित नहीं होता है, ना ही प्रार्थीगण द्वारा उल्लेखित भूमि वादग्रस्त के संदर्भ में अपनी निर्माता/अधिकारिता अथवा हिस्सेदारिता के संदर्भ में कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ना ही प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम का पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज वाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का पक्ष व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार भूमि प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम कभी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर (फॉरेस्ट ट्रेक) आमेर  
सहायक कलेक्टर (फॉरेस्ट ट्रेक) आमेर,  
मुख्यालय, जयपुर